Export of Foodgrains from Visakhapatnam Port

906. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains exported from Visakhapatnam Port in 1994-95;

(b) whether foodgrain exports have registered an increase in 1995-96 from Visakhapatnam; and

(c) if so, the details of foodgrain exports in 1995-96 upto October 31, 1995 from Visakhapatnam?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) During the year 1994-95, a quantity of 6,940 tonnes of foodgrains (Rice) was exported.

(b) and (c) Yes, Sir. A quantity of 1,51,203 tonnes of foodgrains (Rice) has been exported from Visakhapatnam Port during 1995-96 i.e. upto 31st October, 1995.

दिल्ली में मिलावटी पेट्रोल की बिक्री के संबंध में शिकायतें

907. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री नागमणि:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत छह माह के दौरान दिल्ली में मिलावटी और कम तोल के पेट्रोल की बिक्री के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में इन पेट्रोल पम्पों की कोई जाँच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोषी मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ङ) तेल कंपनियों को गत छः माह के दौरान दिल्ली में मिलावटी पेट्रोल की बिक्री के संबंध में एक शिकायत तथा पेट्रोल को कम मापने के संबंध में तीन शिकायतें मिलीं। शिकायतें प्राप्त होने पर जांच-पड़ताल की गई थी तथा उनमें से कोई भी शिकायत सिद्ध नहीं हुई थी।

नदियों में अशोधित अपशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना

908. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री नागमणि:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के आसपास स्थित औद्योगिक एककों द्वारा अशोधित अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाया जाना अभी भी जारी है, हालांकि ऐसा करना वर्जित है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप नदियों का जल और अन्य जल स्रोत अत्यधिक प्रदूषित हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उद्योगों द्वारा अशोधित अपशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने पर विचार किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) सूचना दी गई है कि गंगा नदी में अपना बहिःस्राव निस्तारित करने वाले 68 प्रमुख उद्योगों में से 55 उद्योगों ने बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं तथा 13 उद्योगों को बंद कर दिया गया है। तथापि, निम्नलिखित इकाइयों का संचालन संतोषजनक नहीं है: आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर; करमचंद थापर ब्रदर्स का यूनिट, उन्नाव, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, बरौनी; इस्टर्न डिस्टिलरी, कलकत्ता; गुलमोहर पेपर लि०, कलकत्ता और इण्डियन पेपर एण्ड पल्प लि०, हाजीनगर।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 133 ऐसे उद्योग हैं जो अपने बहिःस्रावों का निस्तारण यमुना और इसकी सहायक नदियों में करते हैं तथा वे

निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं। इन उद्योगों की श्रेणियों का विवरण निम्नलिखित है:

उद्योग की श्रेणी	अनुपालन न करने वाले उद्योगों की संख्या
1. कागज एवं लुग्दी	53
2. डिस्टिलरी	8
3. चीनी मिल	9
4. औषध उद्योग	7
5. इंजीनियरिंग उद्योग	16
6. वस्त्र उद्योग	10
7. रासायनिक उद्योग	1
8. दुग्ध उद्योग	1
9. अन्य	28

(घ) नदियों में बहिःस्रावों के निसस्सारण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) उद्योगों के लिए बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) दोषी इकाइयों के विरुद्ध, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(3) लघु उद्योगों के समूहों में सामूहिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(4) कतिपय अधिसूचित प्रदूषण निगरानी एवं नियंत्रण उपकरणों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

(5) यमुना नदी में देश के प्रमुख नदियों के कुछ अत्यधिक प्रदूषित भागों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना एवं राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू की गई है।

Pressure from P-8 countries on India to sign NPT

909. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether pressures are being mounted by the P-8 Group of developed countries on Government to change its stand on NPT and missile development;

(b) whether the Canadian Government has in a demarche demanded such a change; and

(c) what strategy, if any, has been formulated to deal with this development?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) The Canadian Prime Minister, in his capacity as Chairman of the G-8 group of countries, had written a letter dated 9 September expressing concerns about the effect of missile deployment and further development of nuclear capability on security in South Asia.

(c) Government has conveyed categorically that it does not share the assessement of the G-8 on this matter. Government remains committed to improving relations with all its neighbours. Where differences in perceptions exist, India is willing to engage in bilateral consultations in order to develop a better understanding of each other's concerns. Government keeps the security situation of India constantly under review particularly in the light of developments in the neighbourhood and is committed to taking all necessary measures designed to cope with any threat that may be posed to the security of the nation.